>

19.00 hrs.

Title: Need to extend the benefits of CGHS to the accredited journalists, freelancers and their families.

हमें सदन में मौका तो मिलता है लेकिन कम मिलता है, यहां सरकार हमारी बात नहीं सुनती और वहां बैठे अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें माननीय सांसदों की क्या भूमिका है? जो योजनाएं केंद्र द्वारा दी गई हैं, सांसद चाहते हैं कि उन योजनाओं में उनकी भागीदारी हो, उनकी बात सुनी जाए और उनको निगरानी का मौका दिया जाए। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आखिरी बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि अगर आप अधिकारियों को विश्वासपात्र मानकर इनके बल पर समाज के अंतिम व्यक्ति तक इस योजना को पहुंचाना चाहते हैं तो इस बात को भूल जाइए। आपका जो उद्देश्य है और अगर इसे आप सफल करना चाहते हैं तो जो लोग सदन में बैठे हैं, चाहे वे जिस पार्टी से हैं, इन्हें विश्वास में लीजिए तभी आपकी योजना सफल होगी। अगर आप अधिकारियों पर भरोसा नहीं करेंगे तो यह फ्लाप है और फ्लाप रहेगी।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और बजट का समर्थन करता हूं।

GENERAL BUDGET, 2009-10 - GENERAL DISCUSSION

AND

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL), 2006-07 –Contd.

MR. CHAIRMAN: Now, we further continue our discussion on the Budget (General).

Shri Lalu Prasad.

*m14

श्री लालू प्रसाद (सारण): सभापति महोदय, आपने कृपा की जो मुझे सामान्य बजट पर बोलने का अवसर दिया। प्रणब दा ने जो वर्ष 2009-10 का बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। हालांकि हमारा लिखित समर्थन इस सरकार को दिया हुआ है।

सभापति जी, हम लोग बाहर से सुनते थे और यह निश्चित था कि कौन फाईनैंस मिनिस्टर बनने वाला है क्योंकि 20 मंत्री बनने वाले थे, इसलिये भारी कन्फ्यूज़न था। कई लोग इस पद के लिये कतार में थे लेकिन सब से योग्य इनको मानते हैं। हम लोग पिछली सरकार में थे। पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही थी, उस समय हमारी सरकार ने बड़ी मुश्किल से तमाम भारत के किसानों को उस तकलीफ से बाहर निकाला था। अभी भी मंदी का दौर समाप्त नहीं हुआ है लेकिन आज देश के सामने खतरनाक बात आने वाली है। इसमें सवाल कांग्रेस पार्टी या किसी अन्य पार्टी का नहीं है। आज सवाल भारत की अर्थ व्यवस्था का है जो कृषि पर आधारित है। आज उद्योग-धंधे भी कृषि पर आधारित हैं। किसान और मजदूर तबका भारत के गांवों में बसता है। आज भारत की जनसंख्या 110 करोड़ हो गई है। हमें कितना चावल, कितना गेहूं, कितनी सब्जी, दूध और दही चाहिये?

यह बजट मुखिया को बनाना पड़ता है इसलिए आपने इस ओर जरूर ध्यान दिया होगा। हमारा सारा दारोमदार कृषि के ऊपर निर्भर करता है। यह बजट एक ऐसे समय आया जब देश के लोगों के सामने सूखे का एक भारी संकट आ गया है। जो व्यवस्था आपने अपने बजट में सोची होगी, मैं ज्यादा तह में नहीं जाना चाहता हूं, वह सारी व्यवस्था सूखे की वजह से चरमराने वाली है। इसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए कि सूखे के समय हम क्या ठोस उपाय करेंगे? इसका असर बहुत बुरा होने वाला है और आपको आकाश के ऊपर बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। प्लांटेशन के काम का पीरियड़ खत्म हो चुका है और यह किसानों के खेत में बिछा भी नहीं है। अब चारों तरफ हाहाकार मचने वाला है। अगर किसी किसान ने पानी पटा कर धान लगा भी दिया है तो वह धान गर्मी की भाप से पूरी तरह गल रहा है। यह प्रकृति की सबसे बड़ी मार हमारे सामने आयी है। मैनें कल इलेक्ट्रानिक मीडिया के लोगों से कहा था कि मैं माननीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार जी से मिलूंगा और कहूंगा कि जब हमारी स्थिति अच्छी तो हमने किसानों को गले लगाया और हमने किसानों को समर्थन मूल्य दिया। हमने अपने किसानों को धान का दाम दिया, गेहूं का दाम दिया तो हमारे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गयी और अन्न के मामले में हमारे भण्डार भर गये। हम बाहर से महंगा गेहूं मंगाते थे, लेकिन बाहर की मिट्टी का स्वाद यहां के लोगों को अच्छा नहीं लगता है। यहां के सभी लोग अपनी मिट्टी से पैदा हुए अनाज को ही खाना चाहते हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अन्न है और हमारे अन्न के पूरे भंडार भर गये हैं। जब स्थिति खराब थी तो हमने एक्सपोर्ट पर रोक लगाया था और जब स्थिति अच्छी हुई तो हम फिर से चावल, गेहूं और दाल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कोई आलोचना की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे पास हमारे क्षेत्र के लोग आये थे तो मैनें उनसे पूछा की महंगाई का क्या हाल है? आज लोगों को खाने की थाली में दाल नहीं मिल रही है, आलू महंगा हो गया है। आज जिनके पास ज्यादा खेती है, रोजगार है, नौकरी है, जिनकी ज्यादा तनख्वाह है, जो प्रोफेसर हैं, उनके ही घर में आज दाल मिल रहा है और वही आज दाल का स्वाद ले पा रहे हैं। यानी जो सम्पन्न हैं वही दाल का स्वाद ले पा रहे हैं और भारत की बाकी जनता के घर से दाल नदारद हो गयी है। मैनें उनसे पूछा कि दाल की जगह पर क्या खाते हो तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से साइकिल पर मटरी बांधकर लाते हैं, कोई मटर होता है, जिसे किराव कहते हैं और उसे 22 रूपए किलो लेकर आते हैं। उसी में ज्यादा तेज नमक-मिर्च देकर, पानी देकर गलत तरीके से काम चला रहे हैं।

हुकुम देव यादव जी ने ठीक कहा है। हुकुम देव जी हमारे रिश्तेदार भी लगते हैं। पहले ये लोकदल में थे, लेकिन इन्होंने अपनी कंठी तोड़ दी और बाहरी कंठीधारी हो गये और वहां चले गये। यह कोई बुरी बात या आलोचना की बात नहीं बोल रहे थे। किसान की जो लागत है, उसमें फर्टिलाइजर है, पानी है, उसके खर्च है, लेकिन उसके ऊपर प्रकृति की मार है। हम किसान की पैदावार का उचित दाम नहीं देते हैं, उसे समय पर कर्जा नहीं देते हैं। हम किसान क्रेडिट कार्ड की बहुत बात कहते हैं। सीपीएम ने कलकत्ता में बहुत दिन तक राज किया है और अभी भी वह राज में है। लैंड रिफार्म की बात हुयी, लाखों-लाख परिवार बटाइदारी में खेत जोतता है। जो एब्सेंटी लैंड लॉर्ड हैं, वे कुछ लोगों को जमीन दे देते हैं कि इस जमीन को तुम जोतो, इस पर तुम्हारा कब्जा है, लेकिन उस पर उन्हें लोन नहीं मिलता है।

पैसा कहाँ से आएगा प्रणब बाबू? देश के अंदर अगर समतामूलक समाज हमें बनाना है और बैलेन्स करना है, सभी परिवारों पर ध्यान देना है, तो यहाँ दो तरह की क्लास है। हैव्स और हैव्स नॉट। हैव्स नॉट की थाली में दाल नहीं, मांस नहीं, मछली नहीं, अण्डा नहीं, और बाकी लोग को कुत्तों को खिला रहे हैं। जो हैव्स हैं, उनका कुत्ता अंघाता है और चारों तरफ उसको वॉकिंग भी कराते रहते हैं। ज़रूरी है, करना भी चाहिए। उसको टहलाते भी रहते हैं। देश में समतामूलक समाज कब बनेगा? नहीं बनने का फल यह हो रहा है कि नक्सलिज़्म पैदा हो रहा है, नक्सलाइट पैदा हो रहे हैं। ये नक्सलाइट निकलकर हमें तबाही के कगार पर खड़ा कर रहे हैं। हमें ज़मीन सुधार, लैण्ड सुधार करना है।, जो दौलत पैदा करने वाला है, जो खेती करता है, हाथ से हल चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है, वह मालिक नहीं है। वह बिहार से माइग्रेट कर रहा है जहाँ से मैं आता हूँ। वह जाकर पंजाब में खेती कर रहा है। पंजाब में सिख भाइयों की खेती संभालता है। वह सूरत में जाता है, मुम्बई में जाता है। गज़ब है इस देश का हाल। फिर बंगलौर में जाता है, वहाँ मार खाता है बिहार का आदमी। बहुत अच्छी बात है कि नरेगा कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया और नरेगा के अलावा प्रधान मंत्री सड़क योजना भी चलाई। भारत निर्माण में काफी पैसा भी दिया और आप उसको फिर रिपीट भी करने जा रहे हैं। यह बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इसको बंद नहीं करना है। सर्व शिक्षा अभियान को भी रिपीट किया है। हम समय पर नहीं आए थे लेकिन गाड़ी में गुज़र रहे थे तो रेडियो में आपका बजट भाषण सुन रहे थे। लेकिन यह जो नरेगा का कार्यक्रम है इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसमें हमने कोई गाइडलाइन बनाई है या नहीं। जब इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं तो नहर खुदवानी है जिससे हमें पानी मिले या उससे हमें रिटर्न हो। सड़कों के निर्माण की बात है। लेकिन उसमें हो क्या रहा है कि जो कामकाजी लोग हैं जिस जाति और बिरादरी के लोग मिट्टी से जुड़े हुए हैं, जो नोनिया जाति होती है, जो बेलदार हैं - गैंता चलाता है, कुदाल चलाता है, खुरपी चलाता है, उसको अपनी सोसाइटी बनाकर काम करने का अवसर नरेगा में नहीं है। काम मिला हुआ है बड़े बड़े ठेकेदारों को, जिनके पास मशीन है और कपलर्स जिनके पास हैं। वह मशीन मिट्टी काट रही है नीचे से और मशीन ही सड़क को बराबर कर रही है। फिर यह जो मज़दूर है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए हम क्या चाहते हैं, कैसा समाज बनाना चाहते हैं? हम लोग बोलते थे कि भैंस के मारल भैंसे में। आपने इनकम टैक्स कुछ कम किया, अच्छी बात है। देश का बजट भी देखना है, सब कुछ देखना है। लेकिन हम यह देखना चाहते हैं, भारत यह देखना चाहता है कि क्या मज़दूर मज़दूर ही रहेगा ज़िन्दगी भर? मज़दूर के पीछे, बहुत सी हमारी मज़दूरन बहनें हैं जो बच्चे को टोकरी में ढककर ले जाती हैं। छोटा बच्चा वहाँ पीछे पीछे जाता है। वह देख रहा है कि उसके माता-पिता मिट्टी से जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। तो ये सारी बातें हमारे सामने हैं। भारत में उन मज़दूरों को इनकम-टैक्स-पेई कब बनाया जाएगा, उसके लिए क्या मैकेनिज़्म है? जो कामकाजी लोग हैं - लुहार हैं, बढ़ई हैं, सुनार हैं, जो आर्टिज़न हैं, इन आर्टिज़न का रोज़गार छीन लिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। ये जो बुनकर हैं, जो वीवर्स हैं, बड़ी भारी संख्या बुनकर लोगों की है, अंसारी बिरादरी के लोगों की है पूरे देश में, उसके लिए कोई बात होनी चाहिए। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट हमने लागू की। देश में 90 मुस्लिम डॉमिनेटेड इलाकों को लिया और पैसा भेजा। बिहार में सात जिलों को हमने लिया जहाँ से इम्युनाइज़ेशन, सैनिटेशन, उनका आवास, उनका स्वास्थ्य, इसके लिए आपने पैसा भेजा। पैसा तो भेजा लेकिन एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। यह मुस्लिम डॉमिनेटेड इलाकों का है। इससे भी निचले क्षेत्रों में मुस्लिम रहते हैं। वह ताक रहे हैं कि उनके लिए कब कुछ किया जाएगा। उनको कवर नहीं किया गया है। उनको कवर करने के लिए बजट में कुछ नहीं किया गया है। लेकिन भूल-चूक को आगे सुधारने की जरूरत है। पूरे देश में माइनोरिटी पर इस स्कीम को लागू करना चाहिए। इसका विस्तार और समय पर करने की आवश्यकता है। नरेगा का तात्पर्य नून रोटी, बेकारों को काम देना अथवा बेकारी भत्ता देना। डॉ. राम मनोहर लोहिया जी, चौधरी चरण सिंह जी, कर्पूरी ठाकूर जी, लोकनायक जयप्रकाश जी से हमने सीखा था कि बेकारों को काम दीजिए। इस देश का बेकार काम चाहता है। यदि काम नहीं दे सकते हैं तो बेकारी का भत्ता दीजिए।

महोदय, जो कम पढ़े-लिखे मजदूर हैं, गांव में रहने वाले लोग है, उन्हें कमोवेश काम मिलता भी है और नहीं भी मिलता है, सारे मजदूर माइग्रेट हो कर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। जब दूसरे राज्यों में हमारे यहां के मजदूर जाते हैं तो पंजाब के लोग कहते हैं कि बिहार के लोग आए हैं, ये हमारी खेती संभालेंगे और हमारी आमदनी होगी। यह तो अशिक्षित मजदूरों की बात है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका पढ़े-लिखे लोगों का है। जिस परिवार के पास पैसे हैं, उस परिवार ने अपने बच्चों को पढ़ाया। भारत के बच्चों के पास दिमाग है, ये पढ़ते हैं, इनमें आगे बढ़ने की भूख है। क्या उनके लिए हमने कोई इंतजाम किया है, कोई इंतजाम नहीं किया है। मंदी के मामले में, जितने भी ये कारपोरेट हाउसेज़ हैं, चाहे प्रदेश की बात हो या दुनिया की बात, मेरा भी दामाद सिंगापुर में एक बैंक में काम करता था, उसकी भी वहां से छटनी हो गई। बड़े पैमाने पर छटनी हो रही है। यह जो पढ़ा-लिखा नौजवान है, अगर उसके लिए हमने कोई इंतजाम नहीं किया, तो निश्चित रूप से सड़कों पर आक्रोश फूटेगा। हुकुमदेव जी और हम जैसे लोग अगर उनसे भेंट करने जाएंगे तो निश्चित रूप से वे अपना गुस्सा निकालेंगे।

महोदय, बिहार सूफीयों और संतों का प्रदेश है। बिहार कोई मामूली राज्य नहीं है। जिस समय बिहार का बंटवारा किया जा रहा था, मैं उस बंटवारे के पक्ष में नहीं था। लेकिन चारों तरफ से हमारे ऊपर दबाव पड़ा। उस समय एनडीए की सरकार थी। यह कहा गया था कि बिहार को तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। बिहार को पैकेज दिया जाएगा। बंटवारे की भरपाई की जाएगी। 1 लाख 86 हजार करोड़ रूपये देने का प्रस्ताव हमने भेजा था, लेकिन एक पाई भी एनडीए के शासन में नहीं मिली।

महोदय, मैं डेवलप्ड राज्य के विरोध में नहीं हूं। लेकिन बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश खास तौर से ईस्टर्न यूपी के लिए हम लोग क्या इंतजाम कर रहे हैं? रघुवंश प्रसाद जी ने इसके लिए काफी लड़ाई लड़ी और पिछली यूपीए सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले को 15-20 करोड़ रूपये यहां से भेजा गया। आप लोगों ने काफी रूपया राज्यों को दिया, लेकिन उन्होंने केन्द्र पोषित स्कीमों पर अपना नाम लगाकर वोट लेने के लिए इलैक्शन के समय में अपनी स्कीम चला दी। कोई सस्ता चावल दे रहा है, कोई कुछ और दे रहा है। इस पर स्ट्रीक्टली नजर रखने की आवश्यकता है।

महोदय, राज्यों की माली हालत सुधारने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं। प्रणब बाबू आपसे लोगों को काफी उम्मीदें हैं और हम लोगों को भी उम्मीद है कि आप इंसाफ करेंगे क्योंकि आप काफी इंसाफ पसंद इंसान है, आप में ममत्व है।

महोदय, आज बिहार की हालत क्या है? जब तक पीछे छूटे हुए भाई की स्पेशल केयर नहीं की जाएगी, उसे बराबरी पर नहीं लाया जाएगा, तब तक विषमता कायम रहेगी। बिहार के मुख्य मंत्री अब हर तरफ से बिहार के लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं। वह कहते हैं कि जब तक स्पेशल केटेगिरी नहीं बनेगी, बिहार का तब तक कायाकल्प होने वाला नहीं है। उन्हें जो करना था, वे कर चुके। हम एक स्पेशल केटेगिरी पैकेज चाहते हैं। बिहार में कहां कोई जाता है, कहां कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इनवेस्ट करने जा रहा है? वाटर लोगिंग है, कटोरा बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय नदियों ने बिहार को हर साल तबाही और बर्बादी के कगार पर खड़ा किया है। हमारे नार्थ-बिहार में बागमती, अधवारा, बूढ़ी-गंडक सारी नदियां आता है। वहां मधुबनी एवं दरभंगा का इलाका है, जहां से हुक्मदेव नारायण जी आते हैं। वह इलाका हर साल बाढ़ के तमाचे से गोता लगाता रहता है। कोसी ने सब बर्बाद कर दिया। हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। एक हजार करोड़ रुपया फर्स्ट किश्त में दिया गया, एक हजार मीट्रिक टन चावल और गेहूं देकर सारे देश ने मदद की। किसी ने भेदभाव नहीं किया। उस गेहूं और चावल को बांटा गया। रेलवे विभाग के 45 करोड़ कर्मियों से, रेल के अधिकारियों से एक दिन की तनख्वाह लेकर हमने वहां दी, लेकिन आज भी कोसी में बालू का ढेर है। वहां खेती और स्कूल चौपट हो गए, कॉलेज ध्वस्त हो गए। बिहार सरकार ने आपसे मांग की या नहीं, मैं नहीं जानता हूं। उन्होंने कोई कार्यक्रम बना कर भेजा या नहीं, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन उसे राष्ट्रीय आपदा स्वीकार किया, माना और उसके लिए हर तरह की सहूलियतें दीं। कोसी से जो बर्बादी हुई है, उसमें दिल्ली को आगे बढ़-चढ़ कर मदद करनी चाहिए। यह कोई नीतीश या लालू का सवाल नहीं है, वह आपकी जनता और आपके लोग हैं। हमें सारी चीजों को देखना है। वहां बाढ़ का खतरा बना रहता है। नेपाल से बात करो, हमारे मरहूम नेता, कर्पूरी ठाकुर जी बराबर बोलते थे कि जब तक नेपाल से बात नहीं होगी तब तक बाढ़ का समाधान नहीं होगा। जब बाढ़ आ जाती है तो फिर वाटर लोगिंग हो जाती है। नार्थ-बिहार को हम गार्डन ऑफ बिहार कहते हैं। वहां का लैंड बेस्ट फर्टाइल है, वहां डेंसिटी ऑफ पापुलेशन बहुत ठीक है और हम मारे-मारे चलते हैं। इस स्थाई समाधान के लिए जितनी भी वाटर लोगिंग है, ताल-तलैया में पानी है, उसके निकासी का कार्यक्रम बनना चाहिए और बाढ़ के लिए स्थाई समाधान होना चाहिए। नदियों को लिंक करने की बात चल रही है, नदियां लिंक की जाएं। इसके लिए सोच-विचार किया जा रहा है। भूगोल की जानकारी भी लोगों को नहीं है। दक्षिण की नदी उत्तर से जाएगी और उत्तर की नदी ऊपर से जाएगी और फिर रास्ते में सुंदरलाल बहुगुणा जी मिलेंगे, मेघा पाटकर भी मिलेगी। पानी किस को, कहां मिलेगा, जो व्यावहरिक है, फिज़िबिल्टी है, वही मिलेगा। आपको वहां ऊंचे-ऊंचे डेम बनाने पड़ेंगे। अभी बीजेपी के लोग बोल रहे थे। अनंत कुमार जी इस काम में काफी मेहनत करते रहते हैं। पानी उल्टा का पुल्टा कैसे चढ़ेगा, नदियों को कैसे चलाओगे, कहां से पैसा लाओगे, कहां से ये बात होगी। ये सब बातें चलती रहती हैं। इसके लिए काफी ध्यान देने की जरूरत है। जो कर सकते हैं, वह कहना चाहिए, लोगों को बहका कर नहीं रखना चाहिए। हम कहते रहते हैं कि नदियों को जोड़ेंगे। राष्ट्रीय नदी आपने बना दी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृपा की। चुनाव के पहले कहा कि गंगा राष्ट्रीय नदी है। गंगा का पानी उत्तर प्रदेश हमें छूने नहीं देता। पानी जहां से ओरिजनेट होता है, वहीं से बंट जाता है। हमने बक्सर में पम्प कैनाल बनाया, लेकिन वहां जरा भी पानी नहीं है। पानी का बंटवारा आज तक नहीं हुआ। इसके लिए आप सब को बुलाएं और जो यह पानी का डिसप्यूट है, उसका समाधान करें। आदरणीय देवगौड़ा जी जब प्रधान मंत्री थे, हम किसी की आलोचना नहीं करते।

महोदय, हमारी गंगा नदी का सारा पानी फरक्का में चला गया। बाढ़ आती है, पानी आता है, कितने दिन हमारा पानी नदी में ठहरता है, फरक्का का गेट खोल दिया और सारा पानी फरक्का में चला गया। हमारे यहां के सारे मछुआरे भूखों मर रहे हैं। हमारे यहां आंध्र प्रदेश से मछली आ रही हैं। अगर आंध्र प्रदेश से मछली नहीं आए, तो बिहार में मछली नहीं मिले। आंध्र प्रदेश में फार्मिंग कर के जो मछली बनती है, वहां से ट्रक के ट्रक मछली और अंडे बिहार में आते हैं। गंगा नदी में हिल्सा मछली से लेकर अनेक तरह की जो मछलियां होती थीं, वे अब नहीं मिलती हैं। मछली का करैक्टर है कि वे धार पर लहराकर उल्टी चढ़ती हैं। गंगा सूख गई है। गंगा में मछली ही नहीं हैं। पहले गंगा में बहुत मछली होती थीं। सैकड़ों किस्म की मछलियां होती थीं और वे ही छलक-छलक कर खेतों में जाती थीं। उन्हीं में से गरीब आदमी मछली खाते रहते थे। मेरा निवेदन है कि फरक्का के बारे में आपको राजनैतिक स्तर पर, विदेश मंत्री या प्रधान मंत्री को बात करनी चाहिए और फरक्का का बांध खुलना चाहिए। भारत सरकार इस पर सोचे। यह कोई खास बात नहीं है। फरक्का का बांध खुलना चाहिए। हमारा पानी फरक्का में चला जाता है और फरक्का के गेट बंद कर दिए जाते हैं। इस बार तो बरसात नहीं हो रही है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि नदी में इस बार पानी नहीं रहेगा। नदी सूख जाएगी। नदी में आप इस पार से उस पार पैदल चले जाइए। नदी सूखी है, मल्लाह भूखा है। इन चीजों पर बैठकर विचार करना चाहिए और कोई न कोई हल निकालना चाहिए। आप लोग मंत्री हैं। एक्सपर्ट लोगों की एक कमेटी बनाकर, इस प्रकार के जो भी सवाल हैं, उन्हें हल करने के लिए जो भी हो सकता है, उस पर एक्सरसाइज करनी चाहिए। हम तो बिना मांगे यही सुझाव दे सकते हैं। वैसे तो हमारी जरूरत आप लोगों के यहां है नहीं। जब बुखार होता है, तो उसे उतारने के लिए पुराने चावल और सिंघी मछली का झोल ही काम आते हैं। हम आपके साथी रहे हैं। इसलिए हमें आपका दिल तोड़ने में भी तो दिक्कत होती है। हम उनका दिल नहीं तोड़ेंगे। उनकी भी तो मजबूरी है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं बने, तो हम उनकी बुराई शुरू कर दें। Now I am relaxed. हम लोग काम करते हैं। ...(व्यवधान)

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : आप लोग बूढ़े हो गए हैं और उधर जवान हैं।

MR. CHAIRMAN : No interruptions please.

श्री लालू प्रसाद : हमें बूढ़े बोलतो हो। हम यादव हैं। हमारी उम्र 60 साल है और कहा जाता है कि साठा सो पाठा।

सभापति महोदय, जो कृषि है, खाद है, बीज है, सिंचाई है और भूमि-सुधार हैं, इन सबको ठीक कराइए, ताकि मंदी से मुकाबला किया जा सके।

महोदय, विदेशी बैंकों में जमा देशी धन को निकालने का काम अगर श्री प्रणब मुखर्जी करेंगे, तो यह देश के लिए बहुत कल्याणकारी कदम होगा। नहीं, तो फिर वही बोफोर्स वाली बीमारी फैलेगी। बोफोर्स पर आप लोग कई इलैक्शन हार गए और हम लोग जीत गए। जब कारगिल की लड़ाई हुई, तब बोफोर्स तोपों ने ही काम किया। अगर बोफोर्स तापें नहीं होतीं, तो वे लोग पीछे नहीं हटते। भाजपा के लोग, हम लोग और आप लोग, सब लोग कुबूल कर रहे हैं कि स्विस बैंक में कितना पैसा जमा है और किन सज्जन लोगों का पैसा जमा है और उसे वे कहां से लाए हैं। इस संबंध में उन देशों की सरकारों से बात कर के उसे देश में लाने का प्रयास किया जाए। हालांकि हमें औथैंटिक जानकारी नहीं है और न मैं इसे जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, तथापि जो हमें मालूम हुआ है, उसके

अनुसार हमें ऐसा लगता है कि इसमें गो-स्लो की नीति अपनाई गई है। उस पैसे को विदेशी बैंकों से निकालने में, उन देशों को समझाने में, हो सकता हो कि समय लगे, लेकिन तब तक आप यह आदेश तो कर ही सकते हैं कि जब से देश में स्विस बैंक में जमा पैसे को निकालने की चर्चा हो रही है, तब से कौन-कौन आदमी ने अपने रुपए वहां से निकाले, उनकी लिस्ट प्रकाशित करा दीजिए। यह तो आसानी से किया जा सकता है। पैसा जब बैंक से निकाला गया है, तो यह तो मालूम ही होगा कि किसने कितने पैसे विथड्रा किए। उसका भी आप पता करा लीजिए, तो आपका भी नाम हो जाएगा। बोफोर्स तोप के मामले में जैसे श्री वी.पी. सिंह का नाम हुआ, वैसे ही आपका नाम भी और ऊंचा होगा। आप लोग गवर्नमेंट में हैं। विदेश मंत्री हैं, वे उन सरकारों से बात करें और आपने जिक्र भी किया था कि इस पैसे को देश में लाने का आप लोग प्रयास करेंगे।

है-नहीं है, क्या है। यह सब बात आ जानी चाहिए, लेकिन जिन बातों पर हमको ध्यान देना चाहिए, वह है कि भारत की हमारी गरीबी, गुरबत कैसे मिटेगी। हम फालतू बहस में बहुत जगह लगे हुए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ फैसला दे दिया, समलैंगिक की कुछ बात बोल दी कि आई.पी.सी. में संशोधन कर दो। यह सब पाश्चात्य देश की कल्चर है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Laluji, please conclude. You have already taken 28 minutes.

श्री लालू प्रसाद : कितने मिनट बोलिएगा? स्विस बैंक में जो पैसा है-नहीं है, जिन सज्जनों ने जमा किया है, जिस आर्गेनाइजेशन ने जमा किया है, वह जरूर मिल जायेगा और उसको निकलवा लेना चाहिए, बता देना चाहिए। वह आदमी एक्सप्लेन करेगा कि हमारा बोनाफाइड पैसा है। इंडियन बैंक में हमको डर था, इसलिए स्विस बैंक में लाकर जमा किया है तो इन चीजों में साफ-साफ यह बात हो जानी चाहिए।

बिहार का एक सवाल मैंने कहा कि इसको स्पेशल कैटेगरी कर दीजिएगा तो इससे यह होगा कि उद्योग में कुछ रिबेट मिल जायेगी, सहायता में कुछ मदद मिल जायेगी, बिहार को बराबरी में आने का मौका मिल जायेगा। बिहारी लोग बड़े कमिटेड लोग हैं, सेंटीमेंटल लोग हैं और चाहे आजादी की लड़ाई हो, जो भी हो, यह सवाल किसी आदमी का नहीं है, इसलिए वहां पर आप यह करिये। कोसी के लिए होम डिपार्टमेंट में दिखवा लीजिए कि बिहार सरकार ने किस-किस मुद्दे के लिए पैसा मांगा। उस पैसे को भिजवा दीजिए, इससे वहां के किसानों को सीधा फायदा होगा। नदियों से जो कटाव हो रहा है, बर्बादी हो रही है, विलेज का जो इरोज़न हो रहा है, इसकी रोकथाम करने के लिए इन चीजों को आप करें। देश में जो साधन हैं, आपने जो कहा कि यह सबसे बड़ा बजट है, हम लोग भी मानते हैं कि सबसे बड़ा बजट आपने पेश किया है, लेकिन इसका लाभ गांव के आम आदमी तक निश्चित रूप से जाना चाहिए और उनको मुख्य धारा में लाने की हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए।

जो पढ़े-लिखे नौजवान हैं, जो पढ़े-लिखे टैक्नीकल लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो कम्प्यूटर की शिक्षा लेते हैं, बी.ए. हैं, ग्रेजुएट हैं, एम.ए. हैं, उनमें मारा-मारी चल रही है, उनके लिए इन्तजाम हो। मुस्लिम ब्रदर्स में, महिलाओं में तालीम की घोर कमी को हम लोगों ने स्वीकार किया है। मुस्लिम महिलाओं को, उनकी बेटियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उनको बराबरी में लाने के लिए रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट भी टेबल पर ले करवा दीजिए। पश्मन्दा मुसलमानों को एस.टी. का, ट्राइबल का दर्जा देने के लिए संविधान का अनुच्छेद 341 है, उसमें संशोधन करा दीजिए। इससे लोगों को मालूम होगा कि हमारी सरकार माइनोरिटी के लिए काम कर रही है। उन्होंने बड़ा बढ़-चढ़कर, कन्धे से कन्धा मिलाकर आप लोगों को वोट दिया या हम लोगों को जहां वोट दिया है, सब जगह वोट दिया है, इसलिए इनको मुख्य धारा में हमको लाना है और समतामूलक समाज बनाने में, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सफल होंगे।

इलैक्शन एक्सपेंसेज़ का जो मुद्दा है, इलैक्शन का खर्चा देने से इलैक्शन जब हम लोग लड़ने जाते हैं तो उसी दिन से बही-खाता लेकर हम लोग जाते हैं, क्योंकि रिटर्न देना है। कहां लगाता है, यह आपका काम नहीं है, इलैक्शन कमीशन का काम होता है कि रिटर्न दो-रिटर्न दो।

आपने जो बजट पेश किया है, आपकी नई सरकार बनी है, यह पहला बजट है और इस बजट का हम समर्थन करते हैं और सब लोग इसका समर्थन करेंगे। आलोचना की जहां बात होगी, आलोचना भी करेंगे। अभी तो पहला ही साल है, बीच-बीच में कहीं जरूरत होगी तो आलोचना होगी, हैल्दी क्रिटिसिज्म होगा, कोई लाठा-लाठी नहीं होगी। ...(व्यवधान)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Thank you.

श्री लालू प्रसाद : इस चीज को आप देखिये और जो जरूरी चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, मांग रहा है हिन्दुस्तान। इसके लिए हमको प्रबन्ध करना चाहिए। जितनी भी हमारी कूवत है, जितनी भी हमारी शक्ति है, वह करिये। आप लैंड टू दि टिलर करिये। फंडामेंटल राइट में लोगों को सम्पत्ति रखने का कितना तक अधिकार रहेगा, आप इस पर सीलिंग करिये। आज गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है और चालाकी से यह बहाना बना रहे हैं कि फंडामेंटल राइट के तहत हमको इसका अधिकार है।

मैं अंतिम बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आलू कॉमन सब्जी है। किसान के खेत से बिचौलियों ने सस्ते दाम में आलू ले लिया। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Thank you, please take your seat.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Laluji, I am calling the next speaker. Please take your seat.

श्री लालू प्रसाद : ठीक है। आप चेयर पर बैठे हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं और आपकी आदेशानुसार अब अपनी बात समाप्त करता हूं और बजट का

समर्थन करता हूं।

MR. CHAIRMAN: Thank you very much.

The next speaker is Mr. Suresh Angadi.

*m15

SHRI SURESH ANGADI (BELGAUM): Sir, most of the hon. Members appreciated the hon. Finance Minister's leadership. The Finance Minister is smart and good but his Budget is not all that good. So, I am opposing the Budget.

This Budget is a neutral Budget. This Budget is not having any vision. The farmers and weavers are the two eyes of the country. There is no specific vision for the farmers or for the weavers. They have proposed to set up one handloom cluster both at Chennai and in West Bengal. Even Karnataka is also having most of the weavers. I do not know why Karnataka is neglected. The people of Karnataka are also part of India. Sir, I would request you to consider Karnataka also in this Budget. The whole India is one. It is because most of the leaders from this side and that side appreciated your leadership, I would request you to consider our State also.

I also thank you for extending the farmers' loan waiver scheme till, I think, 31st December. I bring this to your knowledge that during 2007-2008, hon. the then Deputy Chief Minister, Mr. B.S. Yeddyurappa in Karnataka waived the farmers' loan up to Rs.25,000 for each farmer in Karnataka. It accumulated to about Rs.1,718 crore. Many times, the Government of Karnataka requested the Central Government to reimburse this amount. After two to three months, the Central Budget was presented. Hon. Shri P. Chidambaram at that time waived the farmers' loan to the tune of Rs.60,000 crore for the farmers. We are part of India. We requested you to consider the loan waiver of Rs.1,800 crore loan waived by hon. then Deputy Chief Minister, who was also the Finance Minister, and reimburse the amount to the Government of Karnataka so as to take up other projects for irrigation and other things. But till then, this was not considered by the hon. Finance Minister. I would request you to reimburse this amount of Rs.1,800 crore to the Government of Karnataka as early as possible because we are also part and parcel of Government of India and please treat the citizens of Karnataka also as part and parcel of India. So, do not neglect us.

Mr. Chairman, Sir, through you, I want to say that this Budget has not considered any special project. The country is facing acute power shortage. There is no proper power supply in the country. There are no big projects. When power is not produced, the industrial production will go down. Farmers will face problem in their farming community and employment generation will not be there. But in this Budget, there are no big projects for power production and because of this, there will be financial problem, and it may create unemployment also. Hence, I oppose this Budget.

Power is more important today. As the human body requires blood, like that the country requires power. It is because of shortage of power, most of the industries and most of the youths are unable to start their industry, and we are seeing that farmers are also suffering throughout the country.

This morning, in Parliament itself, there was a power cut. In Delhi, all the Members of Parliament, when they go to their residences during night time, feel the heat. If the AC is not on, then only we understand the problem of power shortage.

For that also nothing has been considered by this Government. I request you to take up this special project.

Many times, the former President of India Dr. A.P.J. Abdul Kalam mentioned that this country should take up linkage of rivers. The then hon. Prime Minister Atal Bihari Vajpayeeji made up his mind to start the Ganga-Cauveri Yojana. It was a Rs. five lakh crore project. Just imagine one thing. If this Ganga-Cauveri Yojana has been completed and they are linked, how much water would have flown in the fields of the farmers and at what extent the economy of the country would have increased. Imagine the employment that you would have provided and many of the existing engineers could have been accommodated. Had it been taken up, the brains of our scientists, senior engineers and many officials could have been put in this project. The farmers could have been benefited and the animals would have been helped. The water level of the country is more important. That is also not taken up in this Budget.

Many times, Dr. Abdul Kalam and Shri Atal Bihari Vajpayeeji have mentioned about this Ganga-Cauveri Yojana. You have not mentioned about this project. Had it been implemented, how much benefit we would have received. Twenty-five years ago, China has implemented this river-linking programme. But even after 62 years we did not have it. For long you have been in power. You are the seniormost leader in the Congress Party. I do not know why this project has not been taken up. I think you are just manipulating the figures but not taking up this project.

Shri Atal Bihari Vajpayeeji formulated the Golden Quadrilateral programme and because of that today most of the vehicles are moving very freely and the economy has increased tremendously because of the roads. Unfortunately, in the last five years and in this Budget also, you have not taken up this Ganga-Cauveri Yojana. I would request you to please reconsider this thing and take up Ganga-Cauveri Yojana by linking the rivers. The problems of Tamil Nadu and Karnataka will not be there in the future. My friend is there. We are always facing this problem because of the acute shortage of water. This is most important.

I bring to your kind notice one important thing. Karnataka has been neglected in most of the things. The IIT or the University has not been given. The NSG hub has not been given. Many times, the Government of Karnataka and the Chief Minister requested that NSG hub should be given to Karnataka because of the terrorist activities and other activities. This has been neglected.

My place Belgaum is an important place for the foundries. A foundry cluster should be given for Belgaum. That is more important because we are exporting most of the foundries. In my district the sugar industry should be revived. In this Budget there is no mention for the sugar industry. There is no mention about the farmers.

The Government of Karnataka has sent a list asking for Rs. 1,000 crore for flood relief. Many times, representations have been given to the hon. Finance Minister and even hon. Prime Minister. Even then the amount of Rs. 1,000 crore has not been reimbursed. At that time, hon. Minister Shri Sharad Pawar and the then Minister of Home Affairs Shri Shivraj Patil and hon. Prime Minister also visited Belgaum and seen the flood relief camps at that time. We have requested many times and many times the Government of Karnataka represented and the hon. Chief Minister met the hon. Prime Minister. Even then the reimbursement has not been done. I would request to make that payment to the Government of Karnataka for taking up the new projects. At least in this year the farmers can avail that facility if given.

This is most important for the country's youth. Those who are in Australia are facing problems. There is unemployment problem in the country. Because of the recession there are no jobs. They are quite intelligent. But we are not using their brains, their skills. For that also nothing has been mentioned in this Budget. I would request that for most of the intelligent engineers and youth who are in different countries you may make a scheme and utilise their services for the country. When they are working sincerely in other countries, if you bring them to this country they can work in a still better way and we can produce more and we can make the country very rich.

Apart from this, the farmers and the weavers are the two eyes of this country. I would request you to take up proper measures for these groups. These are the two major categories − one gives food for survival and the other gives clothes for our smartness. These two categories are important. For this you please take up necessary steps.

I thank you for allowing me to speak in this discussion. Since you have not mentioned all these points, I raised them. I like you, Sir. But I do not like your Budget.

*m16

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): सभापति महोदय, आज प्रणब बाबू के बजट की जो प्रस्तुती हुई है, उसके समर्थन पर बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जो लोग कुछ समय से राजनीति में हैं, उनके लिए प्रणब बाबू एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी में जेम्स बांड यानी 007 एजेंट की पिक्चर्स आती हैं, तो प्रणब बाबू हमारे लिए 007 एजेंट की तरह हैं। जब कोई विशेष मुसीबत आती है, तो पूरी सरकार की तरफ से प्रणब बाबू को उस एजेंट के रूप में भेज दिया जाता है। मैंने देखा है कि जब मुम्बई पर हमले हुए थे तब इस सरकार की रक्षा करने के लिए उन्होंने बहुत मुस्तैदी के साथ 007 का रोल अपनाया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब इस दिक्कत का सब पर प्रभाव पड़ा तब भी उन्होंने बड़ी मुस्तैदी के साथ हमारी रक्षा की।

प्रणब बाबू, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप अपने विचारों में उसी तरह की छलांग लगाते हैं, जो 007 का एजेंट लगाता है। हम लोग को एक विश्वास है कि आप हमारे सारथी हैं, हमारा रथ, इस देश के विकास का रथ अपने मुकाम तक पहुंचेगा।

सभापति महोदय, मैं अपने वक्तव्य को तीन भागों में बांटूगा। सबसे प्रथम -- इस बजट पर अपनी टिप्पणी देना चाहूंगा। दूसरा, लालू जी और हमारे कई मित्रों ने अपनी तरफ से जो विचार प्रकट किये हैं, उनके अंदर एक आक्रोश है, एक भावना है। हमारा कृषि और हमारा ग्रामीण क्षेत्र कई वर्षों से उपेक्षित रहा है, उसमें मैं कुछ अपनी बात कहूंगा।

अंत में, तीन प्रोंग स्ट्रैटेजी में प्रणब बाबू ने प्रशासनिक सुधारों की जो बात की थी, उस पर मैं कुछ अपनी बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले मैं यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले छः-आठ महीने में विश्व स्तर पर एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन आया है। कई वर्षों से तमाम पार्टियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि हमारी जो पूर्व में अर्थव्यवस्था होती थी, जिसमें हम अपने आपको दुनिया से बचाकर रखते थे और बरसात में अपने आपको एक छाते की तरह रखते थे, उसमें मिलते नहीं थे, लेकिन एक धारणा बनी कि नहीं, इस देश को थोड़ा सा और खोलना चाहिए। आजादी के 40 साल बाद काफी विकास हुआ। अब हम सुदृढ़ हो गये हैं, अब हम बराबरी से विश्व के साथ मुकाबला कर सकते हैं। उनके साथ संबंध बांध सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं। आज हमारी बेटी बड़ी हो गयी है। वह घर की दहलीज से बाहर निकलकर गली में जा सकती है। जब हमने मंशा ली, तो एक दूसरे विकास की धारणा इस देश में बनी। खासकर

पिछले पांच-सात साल में जबसे डा. मन मोहन सिंह जी की सरकार आयी, जिसमें आर्थिक रूप में चिदम्बरम जी ने और बाद में प्रणब बाबू ने एक सारथी के रूप में इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे चलाया। वर्ष 1991-92 में वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा जो कदम उठाये थे, उससे एक विश्वास इस देश की जनता को हुआ। यही ग्रोथ, यही विकास, जिस पर टिप्पणी की जाती थी, जिस पर कई बार कहा जाता था कि ग्रोथ पर फोकस करना महज एक बकवास है। जो सरकारें केवल ग्रोथ की बात करती हैं, वे केवल पूरे देश को गुमराह कर रही हैं, अलग कर रही हैं। आज चर्चा बदली है। आज इस सदन में कई सी विचारधारा के लोग जो बीजेपी में ही नहीं, दूसरी पार्टियों में भी है, वे बीजेपी और हमारे बीच में बैठते हैं, इस धारणा पर विश्वास करते थे। सामाजिक विचारधारा से जुड़ी पार्टियां भी इस बात को मानने लगी हैं कि विकास तो अनिवार्य है। यह आठ परसेंट, नौ परसेंट और दस परसेंट का विकास इसलिए अनिवार्य है, क्योंकि इस देश की जो जरूरतें हैं, आर्थिक जरूरतें हैं, पैसा खर्च करने की जरूरतें हैं, देश की बदलती हुई आकांक्षाएं हैं, यहां के लोगों की अपने बारे में, अपने जीवन स्तर की अपेक्षाएं हैं, उसमें विकास की एक महत्वपूर्ण जरूरत पड़ेगी। उस विकास की जरूरत को कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए सरकार ने जिस बखूबी के साथ पिछले चार-पांच साल में पूरा किया है, उसके लिए मैं यूपीए सरकार को श्रेय देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा।

पिछले साल एक विषम परिस्थिति रही है। मनीष तिवारी, जो मुझसे पहले बोल रहे थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस बात को समझाया कि कैसे 1920-1921 में दुनिया भर में जब इकॉनामिक डिप्रेशन आया था, तो बैंकिंग वर्ग के कुछ कार्यकलापों द्वारा दुनिया को एक स्थिति में पाया गया था, उसी तरह से हमने भी अपने आपको इस विषम परिस्थिति में पाया।

20.00 hrs.

लेकिन फिर भी दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने के बावजूद, दुनिया की अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई प्रगति से फायदा लेने के बावजूद हमारी सरकार ने, मैं इस मामले में इससे पूर्व की एनडीए सरकार और कांग्रेसी सरकारों की भी सराहना करूंगा ने, पूरे तरीके से विश्व आर्थिक व्यवस्था से नहीं जोड़ा। कुछ रूपों में हमें उससे बचाकर रखा है, तब आज की आर्थिक मंदी में जब दुनिया के बड़े से बड़े देश घिर गए हैं, हिल गए हैं, हमने 6.7 प्रतिशत की दर हासिल की है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Mr. Sandeep, you can continue your speech tomorrow.

श्री सन्दीप दीक्षित : महोदय, मैं एक वाक्य बोलकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि देश आज मुझे उस गली की तरह दिखता है जिसमें भूकम्प आने से सारे मकान गिर गए हैं, लेकिन बीच में एक मकान हमें खड़ा हुआ दिखाई देता है। यह मकान वह था जिसकी नींव डा0 मनमोहन सिंह जी ने वÂाऩ 1992 में रखी थी और जिसकी मरम्मत आज भी डा0मनमोहन सिंह और प्रणब दादा कर रहे हैं। मैं यह चित्र प्रस्तुत करने के बाद बैठता हूं और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मुझे आगे बोलने का मौका आप कल दें।

MR. CHAIRMAN: Thank you, Mr. Sandeep. The House stands adjourned to meet tomorrow, the 10th July 2009 at 11 am.

*t31

19.00 hrs.

Title: Need to extend the benefits of CGHS to the accredited journalists, freelancers and their families.

MR. CHAIRMAN : Now it is 7 p.m. As decided earlier, we may now take up matters of urgent public importance. There are four submissions to made under Zero Hour.

Shri Tufani Saroj.

श्री तूफ़ानी सरोज (मछलीशहर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान भारत सरकार के मुख्यालय पर पत्र-सूचना कार्यालय द्वारा प्रत्यायित पत्रकारों और विशेष रूप से फ्री-लांस पत्रकारों की एक प्रमुख समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इन पत्रकारों और उनके परिवार के सदस्यों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध थी। लेकिन वर्ष 2007 में पहले तो इस सुविधा को समाप्त कर दिया गया और फिर प्रयास के बाद इसे शूरू किया गया तो अस्थाई और वह भी अकेले पत्रकार के लिए किया गया। उनकी पत्नी और बच्चों को इस सुविधा से वंचित कर दिया गया। इस सुविधा के लिए पत्रकारों से 1067 रुपए सालाना लिया भी जा रहा है। सरकार के इस रवैये से सबसे ज्यादा प्रभावित फ्रीलांस और कम वेतन पाने वाले पत्रकार हैं। भारत सरकार का यह रवैया चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों के साथ घोर अन्याय है। अतः हमारी सरकार से मांग है कि वह भारत सरकार के मुख्यालय से प्रत्यायित पत्रकारों को सीजीएचएस के माध्यम से दी जा रही स्वास्थ्य सुविधा को पूर्व की भांति पूरे परिवार के लिए बहाल किया जाए ताकि वे बगैर किसी चिंता के अपना काम कर सकें।